(a) the result of the inquiry ordered into the allegations that certain army personnel had committed excesses in Naga area; and

(b) the action taken thereon?

The Minister of Defence (Shri Krishna Menon): (a) and (b). Both the incidents at PURR and METIKUMI in the Naga area were investigated by two military Courts of Inquiry. The reports are under examination.

पंजीकृत सहकारी आवास समितियां

९०९. { **श्री खुशवक्त राय :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी पंजीकृत सहकारी आवास सोसाइटियां कितनी हैं जिनके पास भूमि नहीं है;

(ख) उनके नाम क्या हैं;

(ग) उन्हें कितनी भूमि की आवश्यकता है;

(घ) उन सोसाइटियों के नाम क्या हैं जिनको सरकार ने भूमि अर्जित करने का आश्वासन दे रक्खा है; और

(ङ) उन सोसाइटियों के नाम क्या हैं जिनके लिये भूमि अर्जित करने की कार्यवाही की जा रही है और वह कार्यवाही कहां तक पहुंच चुकी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). ऐसी १५५ पंजीकृत सहकारी आवास सोसाइटियों के नामों का, जिन्होंने दिल्ली प्रशासन से भूमि प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल टी—३०८६।६१]

(ग) लगभग २,००० एकड़ । सोसाइटियों की भूमि सम्बन्धी आवश्यकताओं की अभी जांच की जा रही है ।

(घ) किसी सहकारी आवास सोसाइटी को कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

(ङ) श्री पी० जी० देव द्वारा नियम १९७ के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के उत्तर में २३ मार्च, १९६१ को सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया । उसमें दिल्ली में भूमि के अर्जन, विकास तथा वितरण सम्बन्धी योजना का विस्तृत विवरण दे दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सारी भूमि प्राप्त की जा रही है । इस भूमि को दिल्ली के व्यवस्थित विकास के लिये प्राप्त किया जा रहा है न कि किसी विशेष आवास सहकारी सोसाइटी के लिये । तथापि यह भूमि प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी सहकारी आवास सोसाइटियों आदि को पट्टेदारी के आधार पर वितरित कर दी जायेगी जिनके दावे प्रामाणिक समझे जायेंगे और जो योजना के अंतर्गत आते होंगे ।

सैनिक सामान का उत्पादन

९१०. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत की कुल आर्डनेंस फैक्टरियों में प्रति वर्ष कितना-कितना सामान और किस लागत का (१) फौज के उपयोग के लिये बनाया गया तथा (२) कितना इतर सेना उपयोग के लिये बनाया गया;

(ख) केवल (१) सेना और (२) अन्य प्रयोजनों के लिये कितने मूल्य का सामान बनाया गया;

(ग) जिन आर्डनेंस फैक्टरियों में इतर सेना उपयोग के लिये सामान बनाया गया

उनमें सेना के उपयोग के लिये बनाये गये सामान में कितनी कमी की गई; और

(घ) क्या यह सच है कि इतर सेना उपयोग के सामान का निर्माण सेना उपयोग के सामान के निर्माण को घटा कर ही हो सकता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णा मेनन) : (क) चूंकि आर्डनेंस फैक्टरियों में विभिन्न प्रकार की कई चीजों का उत्पादन किया जाता है, पिछले तीन वर्षों में उन की विस्तार-पूर्वक राशियां बता पाना संभव नहीं है । सेना के लिए और अन्य प्रयोजनों के निमित्त सभी आर्डनेंस फैक्टरियों में, पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष उत्पादित होने वाले सामान का मूल्य निम्नलिखित है :—

१९५८–५९	१९.५९ करोड़ रुपये
१९५९–६०	२५.१४ करोड़ रुपये*
१९६०–६१	३०.१४ करोड़ रुपये

*कुल उत्पादन के वास्तविक मूल्य के बारे में, अन्तिम आंकड़े नवम्बर, १९६१ के शुरू में प्राप्य हो सकेंगे । इसलिए उपरोक्त आंकड़े अस्थायी हैं और अन्तिम रद्दोबदल के साथ संशोधन अधीन हैं ।

चूंकि अधिकतर हालतों में आर्डनेंस फैक्टरियों में उत्पादन होने वाले सामान की लागत प्रगति-शीलता से कम होती गई है, उत्पादन में वास्तविक उन्नति उत्पादन के कुल मूल्य में उन्नति से कहीं अधिक है ।

(ख) सेना और दूसरे प्रयोजनों के लिए आर्डनेंस फैक्टरियों में उत्पादित सामान का थोक मूल्य नीचे दिया गया है । उसमें भी १९६०–६१ के आंकड़े अन्तिम रद्दोबदल के कारण संशोधन अधीन हैं ।

	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
	(रुपये करोड़ में)		
सेना, वायुसेना, नौ-सेना तथा	१४.३१	१९.९४	२३.२२
एम० ई० एस०	२.०८	१.७५	१.२७
असैनिक व्योपार	३.२०	३.४५	*५.६१

*इस में बार्डर रोडज आर्गेनाइज़ेशन को वितरित किया गया सामान भी शामिल है जिसे दाती निर्गम (पेमेंट इश्यु) शुमार किया जाता है ।

(ग) अन्य प्रयोजनों के लिए सामान तैयार करने के निमित्त सेना के लिये सामान के उत्पादन में कमी नहीं की जाती । प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए उत्पादन को बहुत भारी प्राथमिकता दी जाती है ।

(घ) जी नहीं ।

Utilisation by States of Money for S.C. and S.T. and Backward Classes

911. Shri Kunhan: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) which are the States that have fully utilised the allotted amount for the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes during the Second Five Year Plan period; and

(b) if the States have not fully utilised the amount, the reasons therefor?

The Deputy Minister of Home Affairs (Shrimati Alva): (a) Out of the seven States from whom information has been received, the Government of Maharashtra have utilised the allotted amount in full.